3. Assam
4. Bihar
5. Goa
6. Gujarat
7. Jammu & Kashmir
8. Karnataka
9. Kerala
10. Madhya Pradesh
11. Ashtra (for some Panchayats)
12. Rajasthan
13. Tamil Nadu
14. Tripura
15. Uttar Pradesh
16. West Bengal

Mandays provided through Rural Employment Programmes

480. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the total number of mandays of employment created throughout the country through Rural employment programmes to alleviate poverty during the last Financial Year and the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): An employment of 8081.06 lakh mandays was generated during the last financial year. In the current year, as per reports received from the States/UTs, 4064.55 lakh mandays have been generated till the end of December, 1992.

ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना हेतु लम्बित प्रस्ताव

481. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना के संबंध में सरकार के पास कौन-कौन से प्रस्ताव मंजूरी के लिये लम्बित पड़े हैं,

(ख) उत्तर प्रदेश से प्राप्त कौन-कौन सी योजनायें अनुमोदनार्थ लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जल सप्लाई की लंबित योजनाओं के संबंध में सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता

482. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में स्वंय सेवी संस्थाओं को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के माध्यम से कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पायी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?